ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

विद्यालयी शिक्षा की समस्यायें एवं मुद्द

(PROBLEM AND ISSUES OF SCHOOL EDUCATION)

Dr. Shiv Kant Tripathi

ABSTRACT:
Education is a central means of all-round development of society. Without appropriate Educational system society and country can-not develop in right direction. In present era the quality in school Education a burning question in front of the country. So there are some suggestion to improve the quality of school Education and teacher Education like the reform in the selection procedure of the teachers, vocational training of the teachers (Pre service and In-service), Financial stagnation, improvement in teacher-student ratio, problem of language and teachers should not be engage in the super erogative work and so on. Now emerging a new concept of virtual teachers in private institutions. Other important factor for decreasing quality in school Education is lack of co-ordination among the teacher Education institutions and school Education

वर्तमान परिवेश में समाज के समुचित विकास एवं संवर्द्धन के केन्द्रीय आयाम के रूप में शिक्षा की भूमिका को सभी स्वीकार करते हैं। समुचित शिक्षा व्यवस्था के आभाव में समाज एवं देश का विकास सही व समुचित दिशा में नहीं हो सकता है। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। शालेय शिक्षा एव शिक्षक शिक्षा को लेकर तमाम आयोग एवं समितियों का गठन होता रहा है किन्तु प्रतिबद्धतायें, समस्यायें एवं चिंतायें यथावत बनी हुयी हैं। चाहे 1952 का लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग हो, 1964–66 का कोठारी आयोग हो, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या 1986 की नयी शिक्षा नीति या फिर 1990–92 की आचार्य राममूर्ति कमेटी हो आदि। इन समितियों एवं आयोगों की रोशनी में हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या हमने इन संस्तुतियों को विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की बेहतरी के लिए कहाँ तक स्वीकार किया है।

वर्तमान में शालेय शिक्षा में गुणवत्ता का प्रश्न सम्पूर्ण राष्ट्र के सम्मुख एक यक्ष प्रश्न है। अतः शालेय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत है। यदि इन सुझावों पर गौर किया जाये तो समस्या का तर्कपूर्ण समाधान खोजा जा सकता है?

1. अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में सुधार :

शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रतिबद्धता एवं योग्यता पर निर्भर करता है अतः शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये। चूँकि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज्य का विषय है अतः प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों मे शिक्षकों का चयन एक समेकित राष्ट्रीय तंत्र द्वारा एक समान मानकों के आधार पर होना चाहिये। साथ ही उनके कार्य एवं सेवा की शर्तो को संतोषजनक बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार हो। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों क प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय प्रणाली में समेकित किया जाये।

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

2. शिक्षकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण :

शिक्षकों को मिलने वाला पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण उस स्तर का नहीं है जिस स्तर की अपेक्षा शिक्षाशास्त्र में की जाती है यही वजह है कि शिक्षा में जो गिरावट बतायी जा रही है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही माना जाता है। जबकि इस गिरावट में शिक्षक एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होता है। यदि शैक्षिक योजनाओं, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम निर्माण एवं रणनीतियों में शिक्षक की कोई अहम भूमिका नहीं होती तो वह कैसे अपनी हैसियत एवं हस्ताक्षेप को सुनिश्चित कर सकता है।

3. आर्थिक अवरोध :

शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु भारी मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है। 1964–66 में गठित कोठारी आयोग ने सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च करने की बात की थी। यदि हम पिछले कई वर्षो के बजट का अवलोकन करें तो पाते हैं कि हम **G.D.P.** का 3 फीसदी ही शिक्षा पर खर्च कर पा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षो में सरकार के शिक्षा के मद में खर्च की जाने वाली राशि में ऐतिहासिक कटौती की है। इसमें सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना आदि में कटौती की गयी है। तमाम शिक्षाविद् और अर्थशास्त्री इस बात को एक स्वर से स्वीकार करते है कि यदि शिक्षा में गुणवत्ता लाना है और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है तो सरकार को शिक्षा के मद में कटौती नही करनी चाहिए।

4. शिक्षक–छात्र अनुपात में सुधार :

कोठारी आयोग ने कहा था कि यदि प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना है तो कक्षा में शिक्षक–छात्र अनुपात 1/25 होना चाहिये। यह अनुपात परिषदीय विद्यालयों में आज भी दूर की कौड़ी है। इस कमी को पूरा करने के लिए 1990 के दशक मे एक वैकल्पिक मार्ग खोजा गया था। उस समय यह सुनिश्चित किया गया कि कम प्रशिक्षित पैरा शिक्षक, अनुबंधित शिक्षक तथा शिक्षामित्रों से कक्षा में शिक्षण का काम लिया जाये। यह एक ऐतिहासिक पहल थी किन्तु आज प्राथमिक शिक्षा को शिक्षामित्रों के सहारे छोड़ दिया गया ह। यह अनुचित है तथा इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज भी प्राथमिक शालाओं में पूरे देश में शिक्षकों के लाखों पद खाली है जिन पर शिक्षामित्र और अनुबंधित शिक्षक कार्य कर रहे हैं।

5 भाषा की समस्या :

आज प्राथमिक शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या बस्ते का बोध तो है ही साथ ही भाषा के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी भी एक समस्या है। हमारे अधिकांश बच्चे अंग्रेजी के डर में जीवन जीते हैं। आज प्राथमिक शिक्षा यदि किसी बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है तो वह है भाषायी विस्थापन। भाषायी समझ और विषयी शिक्षण में शिक्षक की अपनी तालीम काफी मायने रखती है क्योंकि जिस तरह आज हमारे शिक्षक प्रशिक्षण या रहे है वे खुद शंका के घेरे में है।

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

6. कर्तव्यातरिक्त कर्म :

आज जितने भी शिक्षणेत्तर कार्य है वे सब प्राथमिक शिक्षकों के कन्धों पर डाले जाते ह। ऐसे में शिक्षक कक्षा में कैसे पढ़ायेगें। शिक्षकों का एक बड़ा समूह है जो पढ़ाना तो चाहता है लेकिन उसे पढ़ाने का अवसर नहीं मिलता है। बाल गणना, जनगणना, पशु गणना, बालिका गणना, भोजन वितरण, चुनाव, वजीफा बाटने जैसे अनुत्पादक कार्यो में लगाया जाता है। शिक्षक स्कूल में पढ़ाना छोड़कर अन्य कार्यो में जुट जाते हैं।

इस प्रकार अनेकों कारक और भी है जो शिक्षण की गुणवत्ता में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की आवश्यकता काफी लम्बे अर्से से महसूस की जा रही थी जो 2015 में पूर्ण हो गयी। प्दजमतदीपच में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। निश्चित रूप से प्दजमतदीपच की अवधि बढ़नी चाहिये थी। जो अब बढ़ चुकी है। प्दजमतदीपच की नयी अवधारणा शिक्षक प्रशिक्षण में कुशल अध्यापकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी।

साथ ही निजी प्रबंधन तंत्र द्वारा संचालित शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं की कार्यप्रणाली को विनियमित किये जाने की आवश्यकता है। जहाँ न तो मानकानुसार शिक्षक है और न छात्रों की उपस्थिति ही संतोषजनक है। निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में **आभासो शिक्षकों** की अवधारणाा जन्म ले रही है। इस समय शिक्षा का गिरता हुआ स्तर निश्चित रूप से चिन्ता का कारण है। चूँकि शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं में तैयार किये गये अध्यापक अन्ततः विद्यालयों में नियुक्त होते हैं। अतः विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम मे तालमेल का होना आवश्यक है।

शिक्षा के गिरते हुए स्तर की एक बड़ी वजह शिक्षकों में व्यावसायिक प्रतिबद्धता की कमी है। शिक्षा व्यवसाय का जो उच्च आदर्श है जैसा कि प्रत्येक व्यवसाय का होता है शायद शिक्षक उस आदर्श से प्रेरित नहीं है? शिक्षा व्यवसाय में वे लोग आ रहे है जिनकी अन्य क्षेत्रों में कोई संभावना नहीं है। लोग अपने अन्तिम विकल्प के रूप में शिक्षा व्यवसाय को अपनाते हैं। ऐसे लोग अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं फलस्वरूप शिक्षा का स्तर दिनोदिन गिरता जा रहा है।

सन्दर्भ :

i. नाईक, जे0पी0, **शिक्षा आयोग और उसके बाद**, पेज नं0 45
ii. शर्मा, प्रेमपाल, **शिक्षा–कुशिक्षा**, पेज नं0 80
iii. प्रपन्न, कौशलेन्द्र, **शिक्षक गुणवत्ता और शिक्षकीय कौशल**, योजना, जनवरी, 2016 पेज नं 0 57